उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राजनीति में बदलती संस्कृति

श्री पूरणमल मीना

सह आचार्य

राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर

सार

2000 के दशक के दौरान, उत्तर प्रदेश (यूपी) में दलितों के बीच राजनीतिक प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यह दशक पहचान की राजनीति के कमजोर होने और साथ ही साथ भाजपा के पुनरुद्धार का साक्षी रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, लेख में तर्क दिया गया है कि यूपी में दलित राजनीति आंतरिक विखंडन, अनिश्चितता और अधिक जटिल चरित्र द्वारा चिह्नित एक चरण में प्रवेश कर चुकी है। उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में दो तेजी से बदलाव दिखाई दे रहे हैं: 2011 के चुनावों में बसपा से भाजपा की ओर; दूसरा, 2013 के अंत से, दलितों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन भाजपा के साथ उनके गुस्से और मोहभंग का संकेत देते हैं। इन तीव्र परिवर्तनों के लिए दो विकास जिम्मेदार हैंरू दलितों के बीच बढ़ती आर्थिक आकांक्षाएं, एक नई अखिल भारतीय चेतना और नेता, वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की जुड़वां ताकतों से प्रभावित। दूसरा, एक नए नेतृत्व के तहत भाजपा का पुनरुत्थान जिसने चतुराई से सामाजिक समावेश और तीव्र आर्थिक विकास के वादे की रणनीति को एक साथ बुना, जिसने दलितों को आकर्षित किया, लेकिन जिसे पूरा करने में भाजपा विफल रही। लेख इस नए सामाजिक गठबंधन के टूटने की ओर इशारा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि केवल प्रतीकवाद की राजनीति 2011 के चुनावों में बीजेपी को दलित समर्थन हासिल करने में मदद नहीं कर सकती है।

मुख्य शब्द: *भारतीय राजनीति, भाजपा का पुनरुत्थान, नए सामाजिक गठबंधन*

परिचय

सहस्राब्दी के पहले दशक के दौरान, दलितों की राजनीतिक प्राथमिकताओं, जिन्होंने हाल के दशकों में उत्तर प्रदेश (यूपी) की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। 1990 के दशक में पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच राजनीतिक चेतना और मजबूत सामाजिक आंदोलनों का उदय देखा गया, जो निम्न–जाति के दलों–समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रभुत्व की ओर ले गया, और पहचान की राजनीति ने चुनावी और जन दोनों को प्रभावित किया। राजनीति। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों, जिन्हें मनुवादी या उच्च–जाति दलों के रूप में देखा जाता है, ने अपने मतदाता आधार में गिरावट का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप निचली–जाति की पार्टियां पहली बार राज्य में सरकार बनाने में सक्षम रहीं। समय। इसके विपरीत, 2000 के दशक में पहचान की राजनीति के कमजोर होने और, हाल के वर्षों में, सामाजिक न्याय, आत्म–सम्मान और गरिमा का समर्थन करने वाली दो निम्न–जाति पार्टियों का पतन हुआ, और साथ ही साथ भाजपा का पुनरुद्धार और मजबूती भी देखी गई।

इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य के खिलाफ, यह लेख तर्क देता है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति हाल के वर्षों में विभाजन, अनिश्चितता और अधिक जटिल चरित्र द्वारा चिह्नित एक चरण में प्रवेश कर चुकी है। यूपी में दलितों की राजनीतिक प्राथमिकताओं में कम से कम दो प्रमुख बदलाव दिखाई दे रहे हैंरू बसपा से विशेष रूप से गैर–जाटव छोटे समूहों द्वारा, 2011 के चुनावों में भाजपा की ओर। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2000 के दशक में, उत्तर प्रदेश में दलितों के बड़े वर्गों के बीच सामाजिक न्याय की इच्छा से आकांक्षा की ओर एक मौलिक बदलाव देखा गया था। हालाँकि, एक दूसरी पारी भी दिखाई दे रही है: 2005 के अंत से, देश भर के दलितों ने अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसने 2008 तक तेजी से हिंसक चरित्र प्राप्त कर लिया, जो भाजपा के साथ बढ़ते मोहभंग की ओर इशारा करता है। ये तेजी से

बदलाव दलितों के बीच आंतरिक विखंडन की ओर इशारा करते हैं; अम्बेडकरवादी और हिंदुत्ववादी दलितों के बीच एक बुनियादी विभाजन है।

2000 के दशक में दो महत्वपूर्ण विकास इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार रहे हैंरू पहचान की राजनीति में कमी, और राज्य में आबादी के सभी वर्गों के बीच तेजी से आर्थिक विकास की इच्छा का फिर से उभरना, लेकिन विशेष रूप से वंचित वर्गों के बीच प्रभावित वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की जुड़वां ताकतें। इसने दलितों के बीच एक नए सामाजिक मंथन को जन्म दिया है जिसने हाल के वर्षों में बढ़ते मध्य/निम्न मध्यम वर्ग, और गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच आंतरिक विभाजन पैदा किया है, साथ ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाली बसपा से मोहभंग भी हुआ है। दूसरा, एक नई पीढ़ी के नेतृत्व में भाजपा का पुनरुद्धार, जिसने चतुराई से हिंदू पहचान के भीतर सामाजिक समावेश के वादे की रणनीति को बुना और सबाल्टर्न हिंदुत्व की अपनी विचारधारा के आधार पर तेजी से आर्थिक विकास किया, जिसने निचली जातियों को आकर्षित किया और भाजपा को कब्जा करने में सक्षम बनाया। राज्य में शक्ति।

यह लेख यूपी की राजनीति में इन बदलावों को समझने की कोशिश करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे उन्होंने 1990 के दशक की तुलना में दलित समूहों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पैटर्न में बदलाव लाया है। यूपी पिछड़ा राज्य है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत के राज्यों की तुलना में वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार बेहतर विकास की ओर नहीं ले गए क्योंकि 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में क्रमिक शासन विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में असमर्थ थे। विशेष रूप से प्रदान की जाने वाली शिक्षा की खराब गुणवत्ता और बढ़ती कृषि संकट की अवधि के दौरान रोजगार प्रदान करने में विफलता पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। नतीजतन, 2000 के दशक की शुरुआत में, आर्थिक परिवर्तन और सुधार की बढ़ती आकांक्षा उन गरीब दलितों के बीच स्पष्ट हो गई, जो खुद को पीछे छोड़ दिया गया महसूस करते थे। 1990 के दशक में राजनीतिक सशक्तिकरण, पहचान और आत्म–सम्मान का एक अंश प्राप्त करने के बाद, दलितों का वर्ग आज एक राजनीतिक दल की तलाश में है जो उन्हें आर्थिक बेहतरी प्रदान कर सके। ऐसी आकांक्षाओं ने उन्हें 2004 के राष्ट्रीय और 2012 के यूपी विधानसभा चुनावों के अभियानों में तेजी से आर्थिक विकास का वादा करने वाली बीजेपी द्वारा लामबंदी के लिए कमजोर बना दिया।

इसी समय, निचली जातियों के वर्ग विशेष रूप से छाटे, गरीब और हाशिए पर रहने वाले दलित समूह, जो हाल ही में मुख्यधारा में आए हैं, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिसमें संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया के दौरान, हिंदुत्व विचारधारा ने कुछ वर्गों को प्रभावित किया है जो श्हिंदूश को व्यापक पहचान का हिस्सा बनने की आकांक्षा रखते हैं। जैसा कि एक अध्ययन तर्क देता है कि श्संस्कृति मायने रखती हैश, यानी सामाजिक संरचना की प्रकृति 'सार्वजनिक क्रियाश पर प्रभाव डाल सकती है और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक और आर्थिक विकास की प्रकृति पर (राव और वाल्टन, 2004)। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृति संबंध के बारे में है – समूहों के भीतर और समूहों के बीच व्यक्तियों के बीच संबंध – और पहचान, आकांक्षाओं, संरचनाओं और प्रथाओं से संबंधित है जो जातीयता जैसे संबंधपरक अंत की सेवा करते हैं। संस्कृति सामाजिक या धार्मिक समूहों के भीतर स्थायी रूप से अंतर्निहित मौलिक घटनाओं का समूह नहीं है। बल्कि, यह निरंतर पुनर्परिभाषा के अधीन निरंतर प्रवाह में विवादित विशेषताओं का एक समूह है

इसलिए, यूपी में हम जो देख रहे हैं वह एक श्राजनीतिक रूप से प्रेरित सांस्कृतिक परिवर्तनश है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक अभिजात वर्ग समूह की संस्कृति के कुछ पहलुओं का चयन करते हैं, उन्हें नया मूल्य और अर्थ देते हैं, और उन्हें समूह (पीतल) को जुटाने के लिए प्रतीकों के रूप में उपयोग करते हैं। । बदलते सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ के जवाब में पहचान निरंतर परिवर्तन और संशोधन से गुजरी है। जबकि बाकी लेख इन विचारों पर चर्चा करेंगे, निष्कर्ष में हम इस सवाल पर लौटते हैं कि क्या महज प्रतीकवाद की यह राजनीति 2009 के चुनावों में बीजेपी की मदद करेगी।

यूपी में 2000 के दशक में निचली जातियों की बदलती राजनीति

2000 के दशक में उत्तर प्रदेश में भाजपा का पुनरुत्थान सामाजिक न्याय पार्टियों के कमजोर होने और कांग्रेस के लगातार पतन के कारण संभव हुआ। बसपा और सपा की एक आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफलता जो राज्य की अर्थव्यवस्था

के आवश्यक तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित कर सके और साथ ही पिछड़ों और दलितों द्वारा सामना की जाने वाली अभावों की विशिष्ट समस्याओं से निपट सके, जो उनके प्राथमिक समर्थन का आधार हैं। मोहभंग और अप्रसन्नता । जहां देश ने 1990 के दशक में बहुत अधिक विकास लाते हुए वैश्वीकरण का अनुभव किया, वहीं उत्तर प्रदेश जाति और सांप्रदायिक राजनीति में फंसा रहा। अध्ययन हाल के वर्षों में चीनी उद्योग में समस्याओं की ओर इशारा करते हैं जिसने पश्चिमी जिलों में छोटे किसानों और मजदूरों को प्रभावित किया है क्योंकि गन्ने की पेराई धीमी होने और कीमतों क कम होने के कारण उन्हें उद्योग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है (दामोदरन और सिंह, 2007)। पारंपरिक उद्योग जैसे पीतल के बर्तन, चमड़ा और ताला उद्योग पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पूर्वी यूपी में, पारंपरिक बुनाई और कालीन बनाने का उद्योग और अन्य छोटे शिल्प और रोजगार के रूप भी गिरावट में हैं (पाई और कुमार, 2012)। दलित समुदायों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव ने उन्हें ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और सांप्रदायिक लामबंदी के प्रति संवेदनशील बना दिया।

उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राजनीति
2. दलितों के बीच राजनीतिक प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन

भाजपा की रणनीतिरू आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समावेशन का वादा

भाजपा द्वारा निचली जातियों की सफल लामबंदी का एक मौलिक कारण इसके शीर्ष नेताओं के बीच पीढ़ीगत परिवर्तन था। 2009 में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए नेतृत्व ने पुराने संस्थापक नेताओं–अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। पार्टी के नेता नामित किए जाने के तुरंत बाद, मोदी ने भाजपा की विचारधारा और संगठन में पर्याप्त परिवर्तन किया । मोदी ने महसूस किया कि यूपी म निचली जातियों के लिए पहचान आधारित लामबंदी के बजाय आर्थिक उन्नति की आकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। साथ ही, यूपी में विजयी शक्ति बनने के लिए पार्टी को पिछड़े वर्गों और दलितों के समर्थन की आवश्यकता थी, जो मिलकर राज्य की लगभग आधी आबादी का गठन करते हैं। इसलिए नए नेतृत्व ने हिंदुत्व की पार्टी की मूल विचारधारा और उसके समर्थन आधार में बड़े बदलाव किए।

1980/1990 के दशक में एक सामाजिक–सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा के रूप में परिकल्पित, हिंदुत्व को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र बनाने और सभी जातियो और समुदायों के जीवन में सुधार करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास के एजेंडे के साथ एक अधिक समावेशी, सबाल्टर्न विचारधारा में विस्तृत किया गया था। विशेष रूप से वंचित। जबकि 1980 और 1990 के दशक में, पार्टी का समर्थन आधार, विशेष रूप से उत्तर भारत में, 2000 के दशक में उच्च जातियों/वर्गों का था, हाशिये पर और कमजोर वर्गों को सहयोजित करने का प्रयास किया गया था। यह गैर–यादव और गैर–जाटव पिछड़े (ओबीसी) और दलितों के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, जिन्हें लक्षित किया गया था क्योंकि वे अब सपा और बसपा के प्रति आकर्षित नहीं लग रहे थे। अधिक सामाजिक रूप से समावेशी पार्टी बनाने के लिए हिंदुत्व को श्गैर–ब्राह्मणवादी हिंदुत्वश के रूप में फिर से परिभाषित किया गया (पाई और कुमार, 2007)। हालाँकि, जबकि ओबीसी के बीच हिंदुत्व के साथ एक सकारात्मक इंटरफेस को यूपी में 1990 के दशक की शुरुआत में देखा जा सकता है, जब उन्होंने भाजपा के महत्वपूर्ण समर्थन आधार का गठन किया और कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और विनय कटियार जैसे हिंदुत्व नेताओं को अपने चरम पर रहते हुए भी प्रदान किया। मंडल प्रवचन। दलितों के एक महत्वपूर्ण वर्ग का हिंदुत्व में बदलाव एक और हालिया घटना है, मुख्य रूप से 2002 से– लेकिन तब से काफी तेजी से हुआ है, जैसा कि 2012 और 2007 के चुनावों के परिणाम दिखाते हैं। हालांकि ये रणनीतियां इन चुनावों के चुनावी अभियानों में स्पष्ट थीं, आरएसएस–बीजेपी द्वारा एक एकीकृत हिंदू पहचान और समर्थन आधार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर शांत लामबंदी वास्तव में 2000 के दशक की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी।

दलित समर्थन हासिल करने के लिए इस नए एजेंडे को लागू करने के लिए दो रणनीतियां बनाई गईं: विकासात्मक और सांस्कृतिक। 2010 से ही मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2004 के चुनावों के लिए एक लंबा चुनावी अभियान शुरू किया और 2012 के चुनावों से पहले एक बार फिर 2011 में राज्य भर में कई रैलियां कीं। यह महसूस करते हुए कि केवल

जाति–गणना पर्याप्त नहीं होगी, मोदी ने अपनी पार्टी के जमीन पर जाति गठबंधन बनाने के प्रयास के विपरीत, कई रैलियों में अपने भाषणों में राजनीति में जाति के विचार की खुले तौर पर आलोचना की, भ्रष्टाचार और धीमी वृद्धि पर हमला किया, और महत्व दिया सुशासन और विकास। 1990 के दशक में अपने प्रभुत्व की अवधि क दौरान विकास प्रदान करने में सपा और बसपा की विफलता ने मोदी को जबरदस्त जगह दी, जिन्होंने निचली जातियों के लिए विकास का पैकेज तैयार किया, जैसा कि पहले की सरकारों ने इनकार किया था।

निचली जातियों की बढ़ती आकांक्षाओं से अवगत, 2004 में, मोदी ने तथाकथित श्गुजरात मॉडलश को जन्म दिया और तेजी से आर्थिक विकास लाने का वादा किया ताकि यूपी बेहतर राज्यों के साथ पकड़ बना सके और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। गरीब वर्ग। गरीबों और वंचितों के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति पिछली राज्य सरकारों को उदासीनता की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने गुजरात में एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी साख के साथ इसका मुकाबला किया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश के गरीब और पिछड़े क्षेत्रों से हजारों प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करता है। आजीविका की तलाश। यह कई मोहभंग ग्रामीणों के लिए एक प्रकाश स्तंभ साबित हुआ, विशेष रूप से पूर्वी हिस्सों में, जो लगातार हिंसा और गैंगस्टरवाद में फंस गए थे, उनके पास अपने राज्य से कुछ भी पाने की बहुत कम उम्मीद थी। विकास को प्रमुख एजेंडे के रूप में पेश करने के साथ, मोदी ने अपनी रैलियों में लोगों को उनका सेवक और देश का चौकीदार होने का आश्वासन देकर मोहित किया (पाई और कुमार, 2005)। इसी तरह, 2007 के चुनावों से पहले, मोदी की चतुराई से नोटबंदी को एक वर्गीय मुद्दे में बदल दिया गया, जो अमीरों से काला धन वसूल करेगा, उन्हें गरीबों का समर्थक बना दिया। संक्षेप में, उन्होंने मतदाताओं, विशेषकर बेरोजगार युवाओं की कुंठाओं और आकांक्षाओं को जगाने पर ध्यान केंद्रित किया।

इसके साथ ही, भाजपा ने गैर–ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की विचारधारा के सांस्कृतिक पहलुओं को एक बड़ी महा हिंदू पहचान के भीतर निचली जातियों को शामिल करने के लिए लागू किया। निचली जातियों को शहिंदूश पहचान के हिस्से की भावना देने के लिए एक बड़ा समर्थन आधार बनाने के लिए उच्च जातियों और ओबीसी और दलितों के वर्गों से मिलकर एक नया हिंदुत्व सामाजिक गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था। ये दोनों समूह जो उच्च जातियों द्वारा प्रताड़ित और भेदभाव किए गए हैं और खुद को हाशिए पर महसूस करत हैं, वे भाजपा द्वारा शामिल किए जाने से खुश थे, जिसे वे एक हिंदू पार्टी के रूप में देखते हैं। नतीजतन, जबकि 1990 के दशक में दलितों के लिए हिंदू उच्च जातियों का विरोध किया जाना एक दुश्मन था, 2000 के दशक में भाजपा ने दलितों को हिंदू धर्म में लाने आर मुसलमानों को एक एकीकृत हिंदू सांस्कृतिक बनाने के उद्देश्य से श्अन्यश बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र। इस प्रयास में, पहचान के बजाय जो पहले सामाजिक संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण थी, आज सामाजिक ईर्ष्या, सांस्कृतिक आकांक्षाएं और आर्थिक चिंताएं प्रेरक शक्तियाँ हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा ने 2004 या 2007 में हिंदू वोटों को सुरक्षित करने के लिए दंगा भड़काने के लिए सांप्रदायिक लामबंदी की अपनी रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया।

भाजपा द्वारा जमीनी स्तर पर लामबंदी के दौरान सांस्कृतिक रणनीति का उपयोग जैसा कि बद्री नारायण ने बताया है, पूरी तरह से नया नहीं है क्योंकि 1990 के दशक के उत्तरार्ध से श्राजनीतिक रूप से प्रेरित सांप्रदायिक ताकतेंश दलितों के बीच चुपचाप और सरलता से काम कर रही हैं । हालाँकि, 2000 के दशक में इसने महत्व ग्रहण किया क्योंकि विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदश में स्थित गरीब और छोटी उप–जातियाँ लोकतांत्रिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगीं। 2000 के दशक के दौरान, स्थानीय हिंदुत्व नेता, जिनमें आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं, स्थानीय इतिहास और मिथकों का पता लगा रहे हैं, जिससे वे दलितो को हिंदुत्व से जोड़ सकते हैं और दूसरा, उन्हें मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। रणनीति धीरे–धीरे उनके और अन्य लोगों के बीच दीवारों का निर्माण करने की रही है जिन्होंने गांवों की समग्र संस्कृति का निर्माण किया था। पहला रामायण के साथ तीन दलित समुदायों को जोड़ने में दिखाई देता है, जिनकी संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक हैरू पासी, मुसहर और निषाद। भगवान राम के प्रतीक को या तो उन्हें जोड़कर, या उनके और एक स्थानीय दलित नायक के बीच समानताएं खोजकर स्थानीय स्तर पर फैलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्थानीय मिथकों को श्रामाइज़श किया जा रहा है इसी तरह, भाजपा ने अंतर–सांप्रदायिक सद्भाव की लोककथाओं को संघर्ष की लोककथाओं के साथ प्रतिरूपित करके मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं विशेषकर दलितों में चिंता पैदा करने का प्रयास किया है, उदाहरण के लिए, बहराइच क्षेत्र में स्थानीय नायक सुहेलदेव के मिथक का इस्तेमाल गाजी मियां के मिथक के खिलाफ किया गया है।

चयनात्मक अतीत के माध्यम से एक नई सामूहिक स्मृति बनाकर दलितों को हिंदू तह में लाने के लिएयह विचार दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करने के लिए है क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में दिखाया जाता है जब यह खतरे में होता है, विश्वास के सच्चे संरक्षक।

लामबंदी की इन रणनीतियों ने बीजेपी को 2009 के लोकसभा और 2007 के यूपी विधानसभा चुनावों में दलितों के बड़े वर्ग का समर्थन हासिल करने में मदद की। 2010 के चुनावों में दलितों के बीच वोटों का बंटवारा स्पष्ट है: बीजेपी को जाटवों का केवल 18 फीसदी वोट मिला, जबकि बीएसपी को 68 आठ फीसदी वोट मिले, लेकिन जाटवों को 45 फीसदी वोट मिले। अन्य दलितों ने बसपा के लिए केवल 29 प्रतिशत छोड़ दिया। 2007 में, प्रतिशत कम था, बीजेपी को 9-4 प्रतिशत जाटव वोट और 38-9 प्रतिशत गैर–जाटव वोट मिले।

बढ़ती दलित दुश्मनी भाजपा से दूर हटो

2004 के बाद या 2005 की शुरुआत में, एक दूसरा चरण दिखाई दे रहा हैरू एक टकराव, जाति आधारित हिंसा और भाजपा के खिलाफ बढ़ती दलित दुश्मनी। दलित वर्गों के समर्थन के आधार पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद, नई सरकार ने इन समूहों के बीच अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए दो रणनीति का इस्तेमाल किया: दलित आइकन डॉ अंबेडकर को उपयुक्त बनाने के लिए, अम्बेडकर स्मारकों के लिए कई आधारशिला रखने के साथ शुरुआत दिल्ली, मुंबई और लंदन में और 2006 में उनके 125वें जन्मदिन पर समारोह; दूसरा, 2005 के दौरान राज्य के राज्यपाल के रूप में यूपी के एक दलित राम नाथ कोविंद का चुनाव। हालांकि, 2010 में भारत भर में कई घटनाएं हुईं, और भाजपा द्वारा उपचारात्मक कदमों की कमी ने दलितों को नाराज कर दिया, जैसे कि मामला हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के खिलाफ और जनवरी 2006 में उनकी आत्महत्या, और मई 2007 में ऊना की घटना, जब गोरक्षकों द्वारा सात दलितों पर हमला किया गया था।

मार्च 2007 में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर जिले में दलितों के साथ दो हिंसक झड़पें हुईं, दोनों ही जाति/समुदाय के प्रतीकों का सम्मान करने के लिए जुलूस निकालने के प्रयासों के कारण हुईंरू दलित–मुस्लिम संघर्ष 20 अप्रैल 2007 को गांव सड़क दुधाली में हुआ एक दलित समूह द्वारा निकाली गई अंबेडकर शोभा यात्रा के कारण। दूसरा, राजपूत–दलित संघर्ष 5 मई 2007 को गांव शब्बीरपुर में राजूतों द्वारा महाराणा प्रताप शोभा यात्रा के दौरान उत्पन्न हुआ (पाई और कुमार, 2007)। जबकि दलित और मुसलमान परंपरागत रूप से सद्भाव में रहते थे, और इन गांवों में राजपूतों के साथ शांति थी, गैर–ब्राह्मणवादी हिंदुत्व पर आधारित लामबंदी ने दलितों को भाजपा समर्थक और बसपा समर्थक और छोटे–मोटे सांप्रदायिक टकरावों में विभाजित कर दिया। गहराते कृषि संकट के कारण आर्थिक चिंताओं के साथ यह हिंसक टकराव का कारण बना, गैर–बीएसपी शासन के दौरान दलितों को एक आसान लक्ष्य प्रदान किया गया (पूर्वोक्त)।

गाँव शब्बीरपुर, जिसने उच्च जातियों द्वारा अत्याचार का अनुभव किया, को पूरे यूपी और अन्य राज्यों के दलितों का समर्थन मिला; भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 21 मई को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 50 हजार लोग जमा हुए, जिन्हें बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी पर (अंगद, 2007)। 20 मई को गांव के 180 दलित परिवारों ने अपने घरों को जलाने के विरोध में बौद्ध धर्म अपना लिया. यूपी सरकार नहीं रोक सकी लगातार जारी जातिगत हिंसारू 23 मई को सहारनपुर में मायावती की रैली से लौटते समय एक दलित की मौत हो गई और 24 मई को एक ठाकुर युवक को गोली मार दी गई और उसे चोटें आईं।

इस घटना के बाद 1 जनवरी को महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर दूर एक गांव भीमा–कोरेगांव में दलितों पर हमले हुए, जहां अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों–हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जिनकी सेना में ज्यादातर महार थे सैनिकों–1818 में ब्राह्मण पेशवा के नेतृत्व वाले मराठा साम्राज्य के खिलाफ। वर्ष 2012 भीमा–कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ थी। दलितों और भगवा झंडे वाले व्यक्तिया के बीच हिंसक झड़पों की सूचना मिली, जिन्होंने पथराव किया। भीमा–कोरेगांव, पबल और शिकरापुर के ग्रामीणों और इस कार्यक्रम का जश्न मना रहे लोगों के बीच झड़पों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए; पुणे और मुंबई में भी झड़पे हुईं।

सबसे महत्वपूर्ण, 2 अप्रैल 2008 को दलित समूहों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन थे, विशेष रूप से हिंदी हार्टलैंड में, सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने में स्पष्ट अनिच्छा और देरी के खिलाफ, जिसमें बदलाव का आह्वान किया गया था। एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पाई, 2008)। उन्होंने महसूस किया कि यह अधिनियम को कमजोर करने का एक प्रयास था जिसका उन दलितों पर मजबूत प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने सरकार से बहुत कम सुरक्षा के साथ अत्याचारों की एक श्रृंखला का अनुभव किया था। जबकि भारत ने अतीत में दलितों द्वारा आंदोलन देखा है, विरोध का पैमाना, हाल के दिनों में शायद अभूतपूर्व था और भाजपा के साथ मोहभंग, नाखुशी और बढ़ते मोहभंग की ओर इशारा करता है। इसने एक नई, अखिल भारतीय दलित चेतना, और जिग्नेश मेवाणी, प्रकाश अम्बेडकर और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा नेताओं को बढ़ावा दिया है, जो जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं; पुराने नेतृत्व द्वारा इस्तेमाल किए गए लामबंदी के विचार और रूप अब अपील नहीं करते हैं। आज दलितों की युवा पीढ़ी परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2013 के राष्ट्रीय चुनाव और 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने समर्थन का इस्तेमाल किया, लेकिन इन चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया।

9 अगस्त 2008 को केंद्र सरकार ने अंततः दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने और अधिनियम के प्रावधानों को बहाल करने के लिए एक विधेयक पारित किया (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 2008बी)। हालांकि, 12द्13 सितंबर 2008 को, आगरा, चित्रकूट, और वाराणसी और कुछ अन्य जिलों में उच्च जाति के हिंदुओं और यहां तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा इस उलटफेर का जोरदार विरोध किया गया था, जिसमें संशोधन को तुरंत वापस लेने की मांग की गई थी देशव्यापी आंदोलन (फर्स्टपोस्ट, 2008)। जबकि भाजपा नेतृत्व ने इन झड़पों को छिटपुट और जिसे वे सुलझा सकते हैं, के रूप में खारिज कर दिया है, विरोध तब आया था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार शुरू हुआ था, जिससे पार्टी चिंतित थी।

इस तनावपूर्ण पृष्ठभूमि के खिलाफ, 14 सितंबर 2008 को कट्टरपंथी भीम आर्मी (या अंबेडकर सेना) के नेता चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई, और मायावती का समर्थन करने, अत्याचारों के खिलाफ दलितों की रक्षा करने और मोदी सरकार को श्उखाड़नेश के लिए जेल से बाहर आने पर उनकी प्रतिज्ञा अधिक टकराव पैदा कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि आजाद पर लगाए गए एनएसए के तहत आरोपों को रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले का उद्देश्य आसन्न विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले दलित समुदाय तक पहुंचना था। लेकिन तुरंत ही, सुप्रीम कोर्ट की शर्मिंदगी से बचने के लिए संभवतरू जल्द ही सुनवाई के लिए एक याचिका में आजाद के खिलाफ कठोर एनएसए को खारिज करन के लिए यह कदम उठाया गया।

दलित राजनीति में ये तेजी से बदलते समीकरण 14 मार्च 2008 को पूर्वी यूपी के गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा के उपचुनावों में और 27 मई 2008 को पश्चिमी यूपी के कैराना में भाजपा की अप्रत्याशित हार से स्पष्ट हैं। जीत सपा–बसपा के पुनरुद्धार और एक साथ आने और राज्य में दलितों और भाजपा के बीच गहराते विभाजन की ओर इशारा करती है। गोरखपुर और फूलपुर में नई सरकार बनने के एक साल बाद ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री मौर्य द्वारा खाली की गई प्रतिष्ठित सीटों पर सपा–बसपा गठबंधन को भारी अंतर से जीत सामाजिक न्याय पार्टियों के लिए एक बड़ी जीत है. (पाई, 2011, 17 मार्च)। 2012 के राष्ट्रीय और 2006 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान, मोदी और आदित्यनाथ ने यूपी को विकसित करने के लिए कई वादे किए थे, जो विशेष रूप से पूर्वी यूपी में गरीबों से अपील करते थे। लेकिन, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों ने दिखाया है, आदित्यनाथ सरकार का अपने पहले साल का विकास रिकॉर्ड मतदाताओं के लिए निराशाजनक साबित हुआ था।

कैराना में, चीनी उद्योग में गहराता संकट, जिसने जाट किसानों को प्रभावित किया, भाजपा की हार का कारण बना (पै, 2008, 4 जून)। हालाँकि, जमीनी रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि दलितों ने परिणाम में एक बड़ी भूमिका निभाई है और भीम आर्मी ने आरएलडी–बीएसपी–एसपी द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित मुस्लिम उम्मीदवार का समर्थन किया है। पूर्वी यूपी में सपा उम्मीदवारों और पश्चिमी यूपी में रालोद उम्मीदवार की जीत से पता चलता है कि बहनजी, जैसा कि मायावती अपने कैडर के बीच लोकप्रिय हैं, दलित मतदाताओं को सपा में जाने के लिए राजी करने में कामयाब रहीं। समान रूप से महत्वपूर्ण, पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच वर्ग प्रतिद्वंद्विता अब जमीन पर महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 1990 के दशक में, इन सामाजिक समूहों के वर्ग गैर–कृषि नौकरियों में चले गए, जिससे उनका एक साथ आना संभव हो गया।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में 2000 के दशक में दलित राजनीति कई चरणों से गुज़री, जिसका राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूपी एक प्रमुख राज्य है जिसने हमेशा भारतीय निकाय राजनीति में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया है; इसने हिंदी पट्टी में पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति से आर्थिक आकांक्षा और आर्थिक उन्नति की इच्छा की राजनीति में बदलाव की शुरुआत की है। परंपरागत रूप से, दलितों ने 1990 के दशक में कांग्रेस के गायब होने के बाद उच्च जाति की पार्टी मानी जाने वाली भाजपा को वोट नहीं दिया था और बसपा का समर्थन किया था। नतीजतन, 1990 के दशक के दौरान, जाति–आधारित पहचान, स्वाभिमान और उच्च जाति विरोधी लामबंदी की आदिम राजनीति ने निचली जातियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को यूपी की राजनीति में केंद्रीयता प्रदान की। ऐसा माना जाता था कि उत्तर प्रदेश हिंदी हृदयभूमि में एक कट्टरपंथी विरोधी जाति–विरोधी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करेगा और गुजरात से अलग था, क्योंकि इसमें धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति के विरोध में दो मजबूत निम्न–जाति दल थे। हालांकि, 1990 के दशक में नीचे से जोर की मजबूत लहर और दलित आंदोलन और इसका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां निचलो जातियों के लिए किए गए कट्टरपंथी वादे को पूरा नहीं कर सकीं, जिससे मोहभंग हुआ और उत्थान की एक नई राजनीति की तलाश हुई।

संदर्भ

1. एडम्स पीसी (1992) टेलीविजन एजिंग प्लेस। ऐन असोक एम जियोग्र 82(1):117–135 (टेलर एंड फ्रांसिस लिमिटेड)
2. अधिकारी एस (1997) राजनीतिक भूगोल। रावत प्रकाशन, जयपुर
3. एडोर्नो (2009) संस्कृति उद्योग पर पुनर्विचार। इनरू थॉर्नहैम एस एट अल (एड्स) मीडिया स्टडीज: ए रीडर (तीसरा संस्करण)। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, एडिनबर्ग
4. अग्रवाल वीबी (2002) (संपा) मीडिया और समाज: चुनौतियां और अवसर। कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन्स इंडिया, नई दिल्ली
5. एग्न्यू जेए, डंकन जेएस (2011) विले–ब्लैकवेल साथी मानव भूगोल के लिए। विले–ब्लैकवेल, लंदन
6. अहमद ए (2009) दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का भूगोलरू एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। अवधारणा प्रकाशन, नई दिल्ली
7. अहमद एएस (1992) बॉम्बे फिल्म्स: भारतीय समाज और राजनीति के लिए रूपक के रूप में सिनेमा। मॉड एशियन स्टड 26(2):289–320
8. अलबरन एबी (2013) सोशल मीडिया उद्योग। रूटलेज, न्यूयॉर्क
9. एंडरसन बी, हैरिसन पी (2010) टेकिंग–प्लेस: गैर–प्रतिनिधित्ववादी सिद्धांत और भूगोल। एशगेट, सरे
10. अप्पादुरई ए, कैरल एबी (1995) पब्लिक मॉडर्निटी इन इंडिया। इन: कंज्यूमिंग मॉडर्निटीरू पब्लिक कल्चर इन ए साउथ एशियन वर्ल्ड (एड), कैरल ब्रेकेनरिज। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा प्रेस, मिनियापोलिस
11. एएसपी के (1998) पदानुक्रम को उसके स्थान पर रखना। कल्ट एंथ्रोपोल 3रू36–49। दृष्टिकोण। एशगेट, लंदन
12. एएसपी के (1990) मेडिएटाइजेशन, मीडिया लॉजिक एंड मेडियार्की। नॉर्डिकॉम रेव 11(2):47–50
13. बैरेट एम (1991) सत्य की राजनीतिरू मार्क्स से फौकॉल्ट तक। राजनीति प्रेस, कैम्ब्रिज
14. बसु ए (2010) न्यू मीडिया के युग में बॉलीवुडरू भू–टेलीविजन सौंदर्यशास्त्र। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, एडिनबर्ग